उपसंहार
उपसंहार—निष्कर्ष एवं सुझाव

उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई ही नहीं है, बल्कि यह प्रदेश विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है। यह स्थान गंगा–जमुनी संस्कृति, आपसी सद्भाव एवं सामान्यायक सौहार्द का वह स्थल है जहाँ विशिष्ट जीवन शैली, व्यवहार, चिन्तन—परम्परा, ऐतिहासिकता, सहिष्णुता, सार्थक सकारात्मक प्रतिविधित्व, विवाह—विनिमय व मनुष्य के हक की लड़ाई का शंखनाद सदियों से होता आया है। इस प्रदेश में ब्राह्मण, क्षatriya, बैश्य एवं शूद्र जातियों समान रूप से निवास करती हैं। आबादी एवं अनुपात की दृष्टि से शूद्र जो वर्तमान समय में अनुसूचित जाति/जनजाति के नाम से जानी जाती है, राजनीतिक भाषा में अनुसूचित जातियों के समूह को “बुझन समाज” का नाम दिया गया है।

देश की लगभग आधी आबादी जिसमें मुख्यतः अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, तथा अन्य पिछड़े, समुदाय स्तर का है, उनका देश की समृद्ध कृषि—भूमि में केवल दस प्रतिशत की हिस्सेदारी है। भारतीय समाज की राजनीति में कमजोरता और दलितों के हित में केवल मानविक सहानुभूति दिखाई जाती है, उनकी समस्याओं के निदान का कोई सार्थक एवं व्यवहारिक हल ढूँढना को प्रयास ही नहीं किया जाता है। बाबा साहब डॉ० भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा ने दलितों के भीतर वैश्वव्यूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध चेतना का सुनिश्चित किया। उनकी भाग्यवादी सोच में परिवर्तन आया। वे एकजुट होकर को प्रयास करने लगे। फलतः दलितों में जहाँ तेजी से जुड़ना स्थान आया वहीं उनके भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी पाने लगी। वे मानवीय अधिकारों के लिए वे प्रतिबद्ध थे और रुढ़िवादी एवं मनुष्यवादी परम्पराओं को दुकान रूप रखे थे। साथ ही साथ राज्य स्तर पर नये नये सामाजिक संगठन बन रहे थे, जिनका तेजी से विस्तार हो रहा था। बीसवीं सदी को दलित चेतना का चरमोत्कर्ष
कहा जा सकता है। विशेष रूप में जब पूना पैकेट के तत्कालिन ज्योंतन विषय को लेकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के आन्दोलन की राष्ट्रीय आधार पर शुरुआत की थी। ब्रिटिश भारत में दलित समाज के लोगों को अपनी बात कहने का बल मिला। परन्तु 1956 में 6 दिसंबर को अम्बेडकर के परिवार में परिवर्तन के पश्चात् आत्मनिर्भर दलित राजनीति का अंतिम हो गया और काँग्रेस पर निर्माण दलित नेतृत्व ने दलित आन्दोलन की पृथक् अस्तित्व एवं अस्तित्व को खण्डित कर दिया। सन् 1957 में दलित आत्मनिर्भर राजनीति की एक अन्य शाखा के रूप में महाराष्ट्र में ही रिपब्लिकन पार्टी का उदय हुआ।

बहुजन समाजपार्टी अपने व्यापक जनाधार के कारण आज भारतीय राजनीति की धुरी बन चुकी है जिसके कारण हर राजनैतिक दल इससे समझौता/गठबंधन करना चाहता है। बसपा बहुजन कम समय में भारतीय राजनीति में सत्ता संपत्ति बनाये रखने का साथ बन गयी है। बसपा को इस बुलदी तक पहुँचाने में मान्यवर काशीराम एवं मायावती के कठिन परिश्रम एवं प्रयास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के वैचारिक आन्दोलन को जीवन पर क्रियान्वित करने का काम किया। वर्तमान समय में बसपा के आन्दोलन की ख्याति राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गयी है। बसपा की मजबूत होती स्थिति ने अप्रवासी भारतीय दलितों को भी अपने समाज की ओर उपमुख होने तथा दलित समाज लिए कुछ करना के पाठ पड़ाया है। आखिर में ये ऐसे कौन से तत्त्व हैं जो इस चेतना को जागृत रखे हुए हैं।

समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञान द्वारा किया जाता है।
समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन और नीतिशास्त्र मानव जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इन शास्त्रों के समान ही ‘राजनीति विज्ञान’ द्वारा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। निर्वाचन आयोग ने 1968 में ‘निर्वाचन प्रतीक आदेश’ के तहत कुछ नियम बनाए जिससे आधार पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख रूप से कांग्रेस दल ने भूमिका निभाई। कांग्रेस का भारत के जन-जन तक प्रभाव था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इस दल का प्रभाव भारत में बना रहा, अन्य राजनीतिक दलों का उद्धव भी इसी राजनीतिक दल के अस्तित्व नेताओं द्वारा किया गया। एक दूर दल विचारधारा के आधार पर अस्तित्व में आए। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं के कुछ भाग को प्रभावित करते रहे कांग्रेस के मतदाताओं की संख्या। अन्य राजनीतिक दलों के पृथक-पृथक मतदाताओं से कम रही। कुछ चुनावों में यह स्पष्ट आकर्षण आए कि कांग्रेस को मिले कुल मत अन्य दलों को मिले कुल मतों से कम थे, इसलिए कांग्रेस के साथ मतदाताओं का बहुमत साथ नहीं रहा फिर भी अन्य दलों की संख्यात्मक अधिकता एवं परस्पर मतभेद से कांग्रेस सत्ता में आती रही। जब भी अन्य दल एक होकर चुनाव लड़े तभी कांग्रेस की हार हुई। उस काल को सर्वाधिक बुद्धिजीवियों ने नवजागरण भी कहा है, वर्तुह असल में यह पुनर्जागरण था, पर सही मायनों में देखा जाए तो वह समय दलितों का अपनी अस्मिता से ब-ब-ब रूपों का भी था। यह भी सच है कि ब्रिटिश भारत में दलित समाज के लोगों को अपनी बात कहने का बल भी मिला था। राजनीतिक ही नहीं सामाजिक और सांस्कृतिक गुणामित्रों से मुक्ति की भाषा पूर्व को नहीं परिचय की हो
देन थी, जिससे दलितों को जीने के अर्थ का पता चला। दलितों में सीमित गति से जागृत होती दुःख संकल्पना आज भारतीय समाज की एक खुली सच्चाई है और यह सत्य है कि यह पूर्व सदी के अन्तिम दस वर्षों में और भी तेजी से बढ़ी है। इस दुःख संकल्पना को हम दलितों के प्रत्येक क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे वे सांस्कृतिक जीवन हो या फिर आर्थिक अथवा राजनैतिक। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में दलितों ने अपने अधिकारों हेतु समृद्ध भारतीय संस्कृति एवं सम्पत्ति पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया, जिसके लिए उन्हें सत्ता संघर्ष करना पड़ा है। इस संघर्ष ने आज सवर्णों को, दलितों को सत्ता के ऊपर चढ़वा पदों पर स्थीर करने पर मजबूर कर दिया है जिसका हम स्वास भी नहीं देखते थे। दलित आन्दोलन की उत्पत्ति को अक्सर लोग डॉ० अम्बेडकर के संघर्ष के साथ जोड़कर देखते हैं जो एक गलत अवधारणा है। वास्तविकता में बाबा साहेब डॉ० अम्बेडकर के पहले भी अनेक दलित समाज सेवियों ने भारत के विभिन्न प्रांतों में संघर्ष किया था। महाराष्ट्र में सबसे पुराने एवं वर्तमान आन्दोलनकारियों में किशन फूर्जी वनसोड़े (1870–1947) गोपाल बाबा बालकर, वी० रवि, मुनिमंडल (1860–1924) कालीचरण नन्द गवली (1886–1962) शिवराम जनबा कांबले (1888–1974) आदि दलित आन्दोलन को आगे बढ़ा दिये थे। (जोगदंड : 1991) दक्षिण भारत में दलित आन्दोलन को दिशा देने वालों में भाग्यरथी वर्मा, एम० सी० राजा, मुरंगाश पिल्ले अयक्तली, अरिये रामारामामी आदि प्रसिद्ध समाजसेवी कार्यकर्ता थे। (जोसफ मैथ्यू: 1986)। उत्तर प्रदेश में आदि हिन्दू आन्दोलन को हवा देने वाला स्वामी अमृतलाल (1879–1933), पंजाब में वसन्त पाई, ठक्कर चन्द, स्वामी शूद्रानन्द एवं मंगूराम थे।
बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संघर्ष के दौरान दलितों को राजनीतिक अधिकार ही नहीं दिलाये, वरन् उन अधिकारों को प्राप्त करने हेतु वैचारिक आधार एवं संगठन भी विकसित किए। सर्वप्रथम उन्होंने सन् 1936 में स्वतंत्रता मजदूर पक्ष (Independent Labour Party=ILP) की नीव डाली। कालान्तर में भारत के विभिन्न प्रांतों को एक सूत्र में पिरोंने के लिए उन्होंने सन् 1942 में ‘अखिल भारतीय श्रद्धूल्ला कास्ट फेडरेशन’ की स्थापना की। उसके पश्चात बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में ही ‘रिपब्लिकन पार्टी’ की रूप रेखा भी तैयार कर ली। इस विषय में उन्होंने राम मनोहर लोहिया एवं अन्य राजनीतिज्ञों से गहरा विचार विमर्श भी किया था, परन्तु उनके अकाल परिनिर्वाण के कारण आरो पीर आई का गठन 1957 में ही सम्बन्ध हो सका। दलित संघर्ष के तीसरे चरण में सन् 1978 में ‘बामसेफ’ (बैंकवर्ल्ड, एण्ड माइनारिटी कम्युनिटीज इम्प्लाइज फेडरेशन) ने दलितों में एक स्वतंत्र नेतृत्व को जन्म दिया जो कांग्रेस विचारधारा एवं पार्टी से अलग थी। आरम्भ में बामसेफ के पास 2,00,000 सदस्य थे जिनमें 15,000 वैज्ञानिक एवं 3,000 डॉक्टर थे। बामसेफ के माध्यम से इसके संस्थापक कांशीराम ने ‘बैक टू दी सोसाइटी’ का नारा दिया, यानी जिन दलितों ने दलित समाज से लाभ लिया है, उनका कर्तव्य बनता है कि अगर वे इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वे समाज को कुछ दे सकते हैं तो अवश्य दें। बामसेफ के कारण दलित आन्दोलन में पहली बार ऐसा हुआ कि दलित मध्यवर्ग भी, स्वर्ण मध्यवर्ग की भांति समाज से लेना ही जानता था, देना नहीं। उत्तर प्रदेश में दलित आन्दोलन का अगर सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाय तो हम दलित आन्दोलन के नन्नी आयामों का आकलन सुगमता से कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम पाएँगे कि इस आन्दोलन ने भारतीय गणतंत्र को मात्र शक्ति ही प्रदान
नहीं की है अपितु इसे और भी अधिक परिपक्व किया है। दलित आन्दोलन की प्रकृति आरम्भ से ही जनतात्मक रही है और इस आन्दोलन ने जनतात्मक शैली से ही अपने अधिकारों की मांग की है। हिस्सा या असंवैधानिक पद्धति कभी भी दलित आन्दोलन का मुख्य आधार नहीं रहा। दूसरी ओर ज्यों-ज्यों दलितों ने संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अपने अधिकारों का प्रयोग करना प्रारम्भ किया है, त्यों-त्यों वे राज्य के काम-काज में भी निर्णायक भूमिका निभाने लगे हैं।

बहुजन समाज पार्टी अपने राजनीतिक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को वर्ण-व्यवस्था, जाति-व्यवस्था तथा मनुवाद का विरोध घोषित करती है और अपने उद्देश्य के अन्तर्गत—“सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के लिए सतत संघर्ष” का उद्देश्य करती है। यह पार्टी “बहुजन समाज” में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों—मुसलमानों, सिखों, ईसाईयों, पारसियों और बौद्धों को समाहित करने का दावा करती है। इसका वैचारिक दर्शन दलित—वेतना जागृत कर देश की जनसंख्या में बहुजन समाज की प्रतिष्ठा के हिसाब से राजसत्ता में हिस्सेदारी एवं राजसत्ता पर प्रभुत्व स्थापित कर पद्धति प्रतिष्ठा वाले ब्राह्मणवादियों एवं मनुवादियों को सत्ता से चुनूर करना है। इनका घोषित नारा है :-

“वोट हमारा राज तुम्हारा— नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।”

बहुजन समाज पार्टी अपनी वैश्विक पृथ्वीमूर्ति को महात्मा ज्योतिबा राव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉ भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर इंजींजीर वीं रामासाम्राज्य के साथ—साथ गौतम बुद्ध, सत्ता कबीर दास, सत्ता रविवाद तथा नारायण गुरु से जोड़ती है तथा इन्हें अपनी पार्टी के इस राजनीतिक चित्तन की विवेचना एवं गवेशणा से दो प्रमुख तत्व एक साथ समन्वित होकर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं—
1. भारतीय राजनीति में जातिवाद।

2. दलित चेतना का उद्भव एवं विकास।

भारतीय राजनीति के अतीत के पृष्ठों के परिशीलन से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी उपर्युक्त दोनों तत्त्व अपने पूरे अस्तित्व के साथ विवादित स्वरूप में गूंजते रहे हैं और निर्विवाद रूप से बहुजन समाज पार्टी का समग्र राजनीतिक दर्शन अतीत की इन घटनाओं एवं परिघटनाओं में सारूर-रूप में सन्निहित है। स्वतंत्रता के पश्चात् भी आरक्षण नीति, संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों के लिए गठित मण्डल आयोग तथा 22 दिसम्बर 1953 को भाषायी आधार पर ‘राज्य पुनर्गठन आयोग’ की स्थापना आदि के सन्दर्भ में दलित चेतना और राजनीति में जातिवाद या जातिवादी राजनीति के अनेक रंग-रूप भी बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक चिन्तन की पृष्ठभूमि का हार खोलते हैं।

देश की राजनीति में निःसन्देह उत्तर प्रदेश की राजनीति की सदा से अपनी एक विशिष्ट भूमिका रही है और आज भी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका का लेखन पर अंकित हो चुकी है जहां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता मायावती के नेतृत्व एवं मुख्य मंत्री में प्रदेश में चार बार पहली बार- 3 जून 95 से 17 अक्टूबर 95 तक 4 माह 12 दिन, दूसरी बार- 21 मार्च 97 से 20 सितंबर 97 तक 6 माह,तीसरी बार-03 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक 1 वर्ष 3 माह 23 दिन, चौथी बार-13 मई 2007 से 15 फरवरी 2012 तक 60 माह (पूरा कार्यकाल) बहुजन समाज पार्टी सत्तासीत हो चुकी है।

ब्राह्मणवाद विशेष विचारधारा दलितों में चेतना उत्पन्न करने का प्रयास करती है, जो दलितों के अपने तथा अन्य वर्णों के सदस्यों के बीच सम्बन्ध को अंकित
करती है। चेतना का स्वरूप दोहरा है। एक ओर जहाँ दलित वर्ग के सदस्यों के बीच व्यवहार एवं दृष्टिकोण तथा हितों की समानता को अनुमान करने से सम्बंधित है, जो उनको अन्यों से अलग के रूप में बोध कराता है, वहीं दूसरी ओर अन्यों द्वारा उनके साथ विषमता पूर्ण व्यवहार का भी बोध करती है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था दलितों का अमानवीकरण करती है, जबकि दलित आन्दोलन सम्पूर्णतर मानवीय हो सकने की आकांक्षा है, इसलिए दलित अमानवीय बनाने वाली व्यवस्था के प्रति विरोध की अभिव्यक्ति करते हैं। ब्राह्मण विरोधी विचारात्मक की एक विशेषता यह है कि इसमें दलितों के मध्य पारस्परिक भाई-चारे पर बल दिया जाता है। भाई-चारे का अर्थ है जिनके साथ तात्त्विक किया जाता है, उसकी प्रासंगिकता में प्रवेश करना। "हम" और "वै" के द्वारा दलितों में दलित सामुदायिकता की भावना का विकास किया जाता है। इसमें "अपने आप" में और "अपने लिए" दोनों प्रकार की चेतना का जन्म होता है। अपने आप में वर्ग वह है जिसमें विभिन्न स्तर यथापेक्षा विभिन्न कार्यकलापों में लगे हुए हैं, परंतु अपने स्थूल सामाजिक तथा सांस्कृतिक बन्धों द्वारा एकताबद्ध है, तथ्यातः वे ब्राह्मण व ब्राह्मणवाद के विरूद्ध एक समूह की रचना करते हैं। बहुजन समाज की क्रांतिकारी अवधारणा ब्राह्मणवाद के असमानता का प्रतिवाद है। 'बहुजन' का प्रयोग सामाजिक प्रस्थिति तथा धार्मिक अनुष्ठान के आधार पर नहीं, अपितु शोषित समूहों के रूप में किया जाता है। बहुजन के केंद्रीय भावना शोषित की है। शोषित ब्राह्मणवाद से हैं न कि पूँजीवाद से हैं। ब्राह्मणवाद की अभिव्यक्ति बसपा के अनुसार आधुनिक मान्यताओं, व्यवस्थाओं, जैसे- राजनीतिक व्यवस्था में भी है। इस प्रकार बसपा ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कार्यपालिका, विधायिका, और व्यावहारिक में भी अविश्वास करती है उनके अनुसार,
इन संस्थाओं पर ब्राह्मणवादी तत्व हारी है। बहुजन समाज के नायक मान्यता कांशीराज जी ने बहुजन समाज को जागृत कर अपने मतों का उपयोग करने तथा उसकी महत्ता को जिस ढंग से समझाकर समाज के सबसे अन्तिम पायदान पर जीवन यापन करने वालों को एकजुट मतदान किये जाने हेतु उत्साहित किया वह न केवल बहुजन समाजपार्टी को लाभ पहुंचाया है, बल्कि भारतीय लोकतन्त्र की जड़ इतनी मजबूत करा दिया है कि वह सत्ता विकास की तरफ अग्रसर होता रहेगा। यह भारतीय राजनीति में एक अविभक्तिपूर्ण योगदान है, इसका उल्लेख निम्नवत है—
(i) बैलेट क्षति बुलेट से ज्यादा मजबूत होती है। (ii) हम वोट की ताकत से इस देश के शासक बन सकते हैं। (iii) वोट का उपयोग कर बहुजन समाज आगे बढ़े। (iv) बहुजन समाज अपने वोट की सुरक्षा करने को आगे आये। (v) वोट बहुजन समाज का सबसे बड़ा हथियार है। (vi) वोटों वालों की बात को आगे बढ़ने के लिए नोटों वालों को पछाड़ें। (vii) स्थिर सरकार नोट वाले नहीं वोट वाले ही दे सकते हैं। (viii) पैगीम्बरी कार्यवाही वोट दान एवं प्रतिशत वाले बहुजन समाज अपनी सरकार बना सकते हैं। (ix) वोट के अधिकार से हम सभी अधिकार हासिल कर सकते हैं। (x) दलितों में राजनीतिक चेतना का ही परिणाम है कि पोलिंग बूथ पर दलितों को लम्बी कतारें, देखने को मिल रही है। वस्त्र पहन गए नारों के दलित चेतना में भावनाओं के पंख लगा दिए, जो शोषित व उपेक्षित वर्गों का आवाज बन गये। इन नारों ने न केवल बहुजन समाज में जोश भरते हैं बल्कि उनके अन्दर जुल्म व ज्यादती के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। बी10 एस10 पी10 के प्रमायोत्पादक नारे निम्नलिखित रूप से दृष्टि के-- 1.बी10 एस10 पी10 करें 2.वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा। 3.बहुजनों का
सच्चा साथी, अपना हाथी अपना साथी। 4.बाबा तेरा मिशान अधूरा, बी0 एस0 पी0 करेगी पूरा। 5.संविधान के सम्मान में, बी0 एस0 पी0 मैदान में। 6.हाथी को वोट दो, बाकी सब को चोट दो। 7. वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 8.बारह गज में हमारा, निवास हजारो एकड़ में मुर्दावाट। 9.आर्य पुत्र होश में आओ, दास प्रथा को मत बढाओ। 10.आर्य पुत्र शर्म करो, दास प्रथा को खत्म करो। 11. मंडल आयोग लागू करो, वर्ना कुर्सी खाली करो। 12.जो जमीन सरकारी है, वह जमीन, हमारी है। 13.जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है। 14. जो बहुजन की बात करेगा, वह दिल्ली से राज करेगा। 15.जाति तोड़ो, समाज जोड़ो।

1989 से लेकर 2009 तक के से विभिन्न लोकसभा चुनाव में बसपा को प्राप्त सीट एवं मतों से उसके क्रमशः बढ़ते हुए प्रभाव व जनाधारा को समझा जा सकता है। सन् 1989 के रूप में बसपा ने कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी। अतः इससे पूर्व लोकसभा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव नहीं था। किन्तु 1989 में बसपा ने प्रथम बार 245 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 3 सीटों पर विजय प्राप्त की, तथा 6213390 मत प्राप्त किया, जो कुल मतों का 2.07 प्रतिशत था। राष्ट्रीय स्तर पर यह बसपा की प्रथम शुरुआत थी जो प्राप्त सीटों एवं मतों के प्रतिशत के तहत से इस सन्दर्भ में नगण्य दिखती है, किन्तु लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करने में सफलता तो प्राप्त कर ही ली। 1991 के 10 वीं लोकसभा चुनाव में 231 सीटों पर लड़कर 2 सीट प्राप्त की तथा 4420719 वोट प्राप्त की जो कुल वोटों का 1.61 प्रतिशत था। जो 1989 में प्राप्त मतों के प्रतिशत (2.07), से 0.46 प्रतिशत कम था। इस प्रकार 1989 में 3, 1991 में 2 सीटों को कायम रखने के बावजूद बसपा अपने जनाधार को कायम नहीं रख सकी, जो इसके प्राप्त मत के प्रतिशत के कमी के रूप में प्रकट हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि बसपा अभी
सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनैतिक मूल्यों और मानकों के मध्य संगतिशील रही। इसी प्रकार बसपा ने 1996 के 11 वीं लोकसभा में 210 सीटों पर चुनाव लड़कर 11 सीटों पर विजय प्राप्त की तथा 13453235 मत प्राप्त करके 4.02 प्रतिशत वोट हासिल कर ली, जो 1991 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 2.41 प्रतिशत मत अधिक थे। इस अवधि में बसपा ने बहुजन समाज के मध्य अपनी बातों को रखने में सफल हुई तथा लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की। निर्धारित ही यह सफलता पार्टी के लिए उत्साहवर्धक रही। 1998 के 12 वीं लोकसभा चुनाव में 251 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटों पर विजय प्राप्त की तथा 17186779 मत प्राप्त की जो कुल मतों का 4.67 प्रतिशत था जो 1996 को अपेक्षा 0.65 प्रतिशत अधिक था। इस बार प्राप्त सीटों की संख्या 6 कम हो गई, जिससे पार्टी में निराशा थी किन्तु मतों का प्रतिशत बढ़ जाने से एक आशा की किरण बनी रही कि पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है क्योंकि प्राप्त मतों के प्रतिशत में धोखा सा ही अन्तर आने पर सीटों की संख्या ज्यादा प्रभावित हो जाती है। पार्टी की महत्वपूर्ण सफलता 13 वीं लोकसभा में 1999 में मिली, जिसमें वोट संख्या, मत संख्या, एवं मत प्रतिशत दोनों कम हुए किन्तु सीटों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। यह भारतीय निर्वाचन पद्धति और जनसंख्या वृद्धि का अद्वैत, संयोग ही है कि मत–प्रतिशत कम होने पर सीटों की संख्या बढ़ गई। इसी प्रकार 2004 के 14 वीं लोकसभा में भी पार्टी ने 19 सीटें प्राप्त करके ये संदेश देने में सफल रही कि अब उसे राजनैतिक सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इस बार उसे न केवल सीट संख्या बढ़ी बल्कि मत प्रतिशत भी 1.77 बढ़कर 5.33 प्रतिशत हो गया। ये सफलता बहुजन समाज में आयी जागरूकता का ही परिणाम है और इसका श्रेय पार्टी प्रमुख को ही जाता है। 2007 (15वीं)
विधानसभा के चुनाव भी भाजपा सम्प्रति एवं बसपा के बीच लड़ा गया। कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। इस चुनाव में बसपा ने बिना किसी इच्छा के गठबंधन से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर अपने पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल पूरा करके मुख्यमंत्री मायावती ने बसपा के रीढ़ (दलितों) जहाँ अपने शासन सत्ता से आर्थिक सहयोग देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया वहीं सवर्णों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें भी आर्थिक देने की बात कही है। 15 वीं विधानसभा में बसपा के पूर्ण बहुमत में आने का तात्पर्य यह नहीं कि केवल दलित ही उनके प्रयास है, बल्कि सवर्णों के दिल में उनके दल के प्रति राजनीतिक आर्थिक का प्रस्फुटन हुआ है।

आर्थिक की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपत्र करेंगे, "सबसे पहले इसकी शुरुआत 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर के छत्रपति शाहीदुहि महाराज ने की थी। इन्होंने अपनी रियासत में दलितों को शिक्षा संस्थानों व अपनी रियासत में दलितों को शिक्षा संस्थानों व सरकारी 50 प्रतिशत आर्थिक की व्यवस्था की थी। इसके बाद आगे चलकर बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने भारतीय संविधान में इनके लिए आर्थिक की व्यवस्था की। लेकिन दुःख की बात यह है कि आर्थिक का जितना लाभ दलितों को मिला हार्दिक था, उतना अभी तक नहीं मिल सका है। अभी तक आर्थिक का कोटा 50 प्रतिशत भर पूरा नहीं हुआ है, जिसका मूल कारण यहाँ मनुवादी पार्टियों की सरकारों का बने रहना है, क्योंकि मनुवादी पार्टियों शुरू से ही आर्थिक की खिलाफ रही है। बहुजन समाज पार्टी, सत्ता में आने के बाद सर्वसमाज के हितों को ध्यान में रखकर देश की आर्थिक नीति तैयार करने की बात बनती है अर्थात् मनुवादी पार्टियों की सरकारों की तरह पक्षपात वाला रूप पहुँच नहीं अपनायेगी, क्योंकि अभी तक यह देखने के लिए मिला है कि मनुवादी पार्टियों की सरकारों में मनुवादी मानसिकता के तहत मुढ़ीमर
आबादी रखने वाले केवल 15 प्रतिशत मनुवाद समाज के हितों को ध्यान में रखकर ही देश की आर्थिक नीति बनाई जाती रही है और 85 प्रतिशत के करीब आबादी रखने वाले बहुजन समाज के लोगों के हितों का कोई खास ध्यान नहीं सखा गया है, जिसके कारण यह समाज लगातार आर्थिक क्षेत्र में कमजोर होता जा रहा है, और बेरोजगारी जैसी विकट समस्याओं से बड़े पैमाने पर जूझ रहा है। 70 प्र. 100 में बहुजन समाज पार्टी करकर की हर नीति 'सर्वजननहिंसात्य, सर्वजन चुकाय' की नीति है। कांशीराम ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति तथा बहुजनों को एक जुट करने के लिए कई संगठनों का निर्माण किया— बैकवर्ड एंड माइनरिटी कम्युनिटीज इंफोलाईक फेडरेशन (यासफब्ज), बुद्धिस्त रिचर्ड केंद्र (बी.आर. री.सी.0), दलित—शोधित समाज संघर्ष समिति (डी.आर. एस.एफ.), तथा बहुजन समाज पार्टी है। इन संगठनों का अपना इतिहास है आन्दोलन के विकास के अवस्था के ये परिणाम है। बसपा की अवस्था तक पहुँचने में कांशीराम को स्वयं कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ा। इन अवस्थाओं से गुजरते हुए वे स्वयं की चेतना के निर्माण से संगठन के निर्माण तक पहुँचे। जिसमें कई कदु अनुभवों से गुजरना पड़ा। ये कदु अनुभव उनके जीवन और उनके आन्दोलन के दिशा निर्धारक बने। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने मार्च 2004 में पहला चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, और कहा है कि आत्म दलों की तरह पार्टी हर चुनाव में अपनी नीतियों, लक्ष्य, या वादे नहीं बदलेगी। पार्टी के घोषणापत्र मन्त्री—मतजज कैसे मुद्दों नहीं हैं। हां मनुवाद की व्याख्या अवस्था है। घोषणापत्र की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि 'मनुवाद' एक ऐसा वाद है जो अन्य सभी ढांढों को नष्ट कर देता है और जिसके कारण, बहुजन समाज के लोग हर प्रकार की समस्याओं से परेराहैं रहे हैं, परन्तु अज्ञातता के कारण हमारे कुछ लोग भी यह
सोचते रहे हैं कि हमारी समस्याओं का हल मार्क्सवाद, समाजवाद, या साम्यवाद में है। पार्टी का मानना है कि जिस देश में मनुवाद मौजूद है उस देश में कोई भी अन्य वाद सफल ही नहीं हो सकता है। घोषणापत्र में पार्टी के दर्शन और उसकी विचारधारा का खुलासा है। घोषणापत्र में कहा गया है कि बसपा का लक्ष्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक गैरवरायरी को जड़ से समाप्त करना एवं मनुवादी व्यवस्था के तहत उपेक्षित बहुजन समाज को समृद्ध और शाक्तिशाली बनाना है, जिसे राजनीतिक सत्ता की मास्टर चामी को हासिल किये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता।

राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का अध्ययन, चुनावों से पूर्व उसके द्वारा जारी किये गये चुनाव घोषणा पत्रों के आधार पर किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के घोषणा पत्र के अन्तर्गत बहुजन समाज के कल्याणकारी कार्यों को कार्यांशित किये जाने को प्रमुखता प्रदान की गयी है।

बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों के अन्तर्गत दलित चेताना के लिए बहुजन समाज पार्टी के ऐतिहासिक महापुरुषों— पेरियार, रविदास, छत्रपति साहूजी महाराज, श्री नारायण गुरु स्वामी, बाबा साहब भीम राव अमबेडकर, के नाम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक़क़, नाटक, वाद—विवाद, अमबेडकर मेला, पेरियार मेला, शाहूजी महाराज मेला, आदिवासी मेला, उनके नाम पर विरहा, धोबिया गृह, कबिताएँ, बाबा साहब के नाम पर डॉ. अमबेडकर गौरव समारंभ, दलित बस्तियों को डॉ. अमबेडकर ग्राम, उनकी मृत्यु अनावरण, उनके नाम पर चौक, पार्क, एवं लोककल्याणकारी योजनाओं, पत्र—पत्रिकाओं, पार्टी के सी10 डी10, इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रचार किया जा रहा है।
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बहुजन समाज अब चैतन्य और जागृत हो चुका है जो न्याय, समान और अधिकार की लड़ाई में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। यह समाज अब अपने शुभविन्तकों और दुस्रों को पहचानने में सक्षम है। अब जो भी लोग मिशन के रास्ते में अड़चन पेदा करेंगे अथवा दलित/बहुजन हित का सौदा करेंगे उन्हें समाज क्षमा नहीं करेगा। न्याय की लड़ाई जो महात्मा फुले ने शुरू की और जिसे बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर, शाहूजी महाराज, पेरियारजी जैसे महान समाज सुधारकों ने आगे बढ़ाया, उसका नेतृत्व अब मान्यवर कांशीराम जी और सुभ्री मायावती के कुशल हाथों में है। अब बहुजन समाज के लोग डरने, झुकने अथवा बिकने वाले नहीं हैं। मायावती सरकार का पतन दलित आकांक्षाओं का अन्त नहीं, बल्कि एक नये इतिहास की शुरुआत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी को मिली प्रचंड सफलता ने जहाँ दलित रेतना की सफलता का एक वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत किया है वहीं विधानसभा चुनाव 2012 में बहुजन समाज पार्टी को मिली असफलता ने बसपा प्रमुख सुभ्री मायावती को यह सोचने का एक अवसर दिया है कि किन कमियों के कारण जनता बसपा सरकार से रुष्ट हुई? क्यों वह ठीक प्रशासन, गुण, बदमाशों एवं माफिकों से साथ नर्मी बरतने वाले श्री मुलाम रिंह यादव की समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की शासन-सत्ता सौंप दिया? यह एक विचारणीय प्रश्न है, जिसे सुभ्री मायावती जी द्वारा खुले दिमाग से लोकतांत्रिक मान्यताओं एवं परम्परा के आलोक सिंहावलोकित करना पड़ेगा।
सुझाव :-

विवेच्य शीर्षक 'उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका-1990 से अद्यतन' पर प्रस्तुत शोध प्रबंध के समग्र अध्ययन एवं निष्कर्ष के पश्चात हम यह देखते हैं कि 4 अप्रैल, 1984 को स्थापित बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में तीन बार गठबंधन सरकार और वर्ष 2007 में जनता द्वारा प्राप्त प्रचंड बहुमत से चौथी बार अपने दम पर सरकार बनाने में सफल हुई। वर्ष 2012 में सम्पन्न उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को मिली कारी हार के परिणाममें बहुजन समाज पार्टी एवं पार्टी मुखिया सुश्री मायावती जी के लिए इस शोध प्रबंध के माध्यम से निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं-

1. बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज को मात्र वोटबैंक के रूप में प्रयोग न करें।
2. बहुजन समाज के सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए बहुजन महापूर्वों के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनकी स्मृति में ग्रामीण तर पर 'उत्सव/कार्यक्रम' आयोजित कराये जाने की परम्परा को कायम किया जाय, जिससे अनमोल एवं गैंगा लोगों में भी अपने समुदाय के प्रति चेतना विकसित हो सके।
3. बहुजन समाज के होनहार युवकों को उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, प्रशासनिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रबंधन शिक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी द्वारा 'दलित शैक्षिक उत्साह' फाउंडेशन बनाकर गाँव के साधन विहीन दलित समुदाय के होनहार बच्चों को लाभान्वित किये जाने की बहुजन कल्याण योजना के कार्यनिष्ठ में आयी गिरावट एवं कमियों पर विशेष निगरानी रखा जाय क्योंकि आज सरकार की योजनाओं का लाभ मात्र दलित समुदाय के उन्हीं लोगों को मिल पाता है, जो या तो
सरकारी सेवाओं में हैं या फिर राजनीति या व्यवसाय में संलग्न हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले लगभग 80 प्रतिशत दलित समाज हरवाही, मजबूरी, रिक्शा चलाने तथा बड़े किसानों के घर पर बेगार करके अपनी जीविका चलाते हैं। 'अम्बेडकर फाउंडेशन' के विषय में दलित समुदाय के नवजुव्वकों को सम्पर्क जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

5. बहुजन समाज पार्टी को 'बामसेफ' से उसी प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहिए जिस प्रकार 'राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ' का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश में 'बामसेफ' ने बहुजन समाज को जागृत करने का ऐतिहासिक प्रयास किया है और इस दिशा में आज भी अग्रसर है।

6. बहुजन समाज पार्टी को 'बामसेफ' के साथ आत्मा और शरीर का संबंध स्थापित करना चाहिए। बहुजन समाज की मुखिया को बामसेफ के हर कार्यक्रमों में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि बामसेफ एक विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी मात्र एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल को विचारधारा से ही आक्सीजन मिलता है। अतः सूची मायावती जी को चाहिए कि इस बहुजन समाज की आत्मा के आत्मसात करें ताकि बहुजन समाज पार्टी को भारतगण राज्य के हर ग्रामों में उत्तर प्रदेश जैसी सफलता की बुनियाद पड़ सके।

7. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को चाहिए कि वह जब सरकार में हों तो जनता से सीधे ‘रु-बुर’ होने के लिए ‘जनता दर्शन’ की परमपरा को लागू करें ताकि जनता उनसे मिल कर अपना दुःख-दर्द कह सके।

8. बहुजन समाज पार्टी को चाहिए कि वह 'बहुजन-दर्शन' पर अमल करते हुए ही आगे बढ़े, क्योंकि पार्टी का दर्शन ही उसकी पहचान हुआ करता है। यदि बहुजन समाज पार्टी अपने दर्शन से हटी तो उसे भी भाजपा जैसी अफकता का सामना
करना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा द्वारा अपने दर्शन से हटने, सत्ता की प्राप्ति के लिए दलों के समूह के आगे नतमस्तक हो जाने के कारण उसे कुछ समय के लिए सत्ता तो गिलिलेङ आज 'राष्ट्रीय परिदृश्य' पर दृष्टि डालने से लगता है कि भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक धिंतन एवं दर्शन से हटने के कारण, उसे न राम मिले और न ही रहीम। इस लिए बसपा को भाषण की इस ऐतिहासिक गतिविधि से सबक लेकर अपनी मूल विवादाध्यक्षा एवं दर्शन पर ही विकसित भारत की बुनियाद के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

9. बहुजन समाज पार्टी को प्रमुखता के साथ जनता की समस्याओं को लेकर जन आन्दोलन के लिए अग्रसर होना चाहिए।

10. बहुजन समाज पार्टी को चाहिए कि टिकट बंटवारे के समय पार्टी के पुराने एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्रमुखता प्रदान करना चाहिए। उन्हें कमजोर वित्तीय आधार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य न मान लिया जाय।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारत वर्ष में एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक विवादाध्यक्षा है, इसे दलित महापुरुषों के समन्वय को दृढ़गति से हुए अपने कदम—फूँक—फूँक कर रखना चाहिए एवं पार्टी में कैड्रबेस तैयार किया जाय ताकि एक के बाद एक वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर लोग बहुजन समाज की पताका को पकड़ते रहें ताकि भाजपा जैसी दुर्गति बहुजन समाज को देखना न पड़े क्योंकि श्रीमान अर्नाक विहारी बाजपेयी के बाद भाजपा का कोई सर्वभावन्त नेता न होने के कारण न केवल भाजपा का नुकसान हुआ है बल्कि भारतीय लोकतंत्र का ढाँचा भी कमजोर हुआ। यदि भाजपा में भी कैड्रबेस नेताओं की परम्परा होती तो आज देश घोटाले बाज एवं भ्रष्टाचारियों के समूह 'कांग्रेस' सरकार से निजात पा सकता था। इस लिए बहुजन समाज पार्टी को इन घटना क्रम से सीख लेते हुए अपने हर राजनीतिक कदम फूँक—फूँक कर रखना चाहिए।